

>

Title : Need to lessen tax on petroleum products for reducing the burden on consumers in the country.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): देश में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के कारण कई वार्षिकों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। सदन में भी महंगाई पर खूब चर्चा होती है पर सार्थक नतीजे कम ही निकलते हैं क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों की अपनी दलील होती है कि वे निरंतर घाटे में चल रही हैं लेकिन ऐसा कम ही होता है। यह बात पेट्रोलियम कंपनियों के वार्षिक रिपोर्ट से साफ होता है जिसमें वे मुनाफा दिखाती हैं।

पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि से देश का हर आदमी किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्यों ने अपने विभिन्न टैक्स लगाए हैं। कर्ण का भार पेट्रोलियम पदार्थों पर देश में इतना अधिक है कि वह मूल कीमत से 28 फीसदी से अधिक दर पर बाजार में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। पेट्रोलियम पदार्थों से यदि टैक्स कम कर दिया जाए तो अगले कुछ वार्षिकों तक पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि पर विराम लग सकता है।

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इस दिशा में कदम उठाए और कम से कम टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाना सुनिश्चित करें जिससे उपभोक्ताओं को बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों से राहत मिल सके।